राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

रोहित ने टिवट्र पर दिया अपने नॉट आउट होने का सुबूत
>> 12

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 19

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 29 जून 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

सरोकार

बिना टूथपेस्ट दांत चमकाएगा पुआल-कोयले का टूथब्रश

जमशेदपुर : जमशेदपुर की कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की इकाई यंग इंडियंस का आइडिया सफल हुआ तो जल्द पुआल की डंडी और कोयले के चूर्ण से बना टूथब्रश आपके सामने होगा। ये दोनों ही पदार्थ न सिर्फ आपके दांतों को सेहतमंद बनाएंगे बल्कि आप प्लास्टिक के उपयोग से भी बच सकेंगे। (पेज-13)

जागरण विशेष

यहां हिंदू रोशन करते हैं चिराग मस्जिद में

समराला : पंजाब के लुधियाना जिले के हेडों बेट गांव में आजादी से पूर्व की बनी मस्जिद सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। गांव में कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं है, लेकिन चिराग रोशन रोज किया जाता है। किसान प्रेम सिंह और गांव के लोग करते हैं मस्जिद की देखभाल। (पेज-13)

ट्रंप के बदले सुर, बोले-भारत से इतने करीबी रिश्ते कभी नहीं रहे

जापान में मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त कहा, लोकसभा चुनावों में जबरदस्त जीत की दी बधाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पहले धमकी देना और कुछ ही घंटे बाद सुर बदल लेना, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है। शुक्रवार को भी वह इसे साबित करते दिखे। भारत को अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाने की धमकी देने के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप की मुलाकात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई तो उनके सुर बिल्कुल बदले हुए थे। जापान के शहर ओसाका में समूह-20 की बैठक से पहले इस भेंट में ट्रंप ने मोदी को दोस्त कहा और चुनावों में जीत की बधाई दी। यह भी कहा, 'भारत व अमेरिका अभी जितने करीब हैं, उतने इतिहास में कभी नहीं रहे।' वार्ता बेहद खुले माहौल में हुई और दोनों ओर से तल्खी भरे मुद्दों को उठाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई।

ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जो जानकारी दी गई है उससे साफ है कि कारोबार से जुड़े मुद्दे काफी हावी रहे। दोनों नेताओं ने इन मुद्दों पर चिंता जताई और फैसला किया कि सीमा शुल्क से जुड़े मसलों पर फैसला करने के लिए जल्द ही दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक होगी। विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया, 'अमेरिका की तरफ से भारत को वरीयता प्राप्त व्यापार साझीदार देशों की सूची से हटाने और अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने का मुद्दा उठा, लेकिन यह हो चुका है। अब इसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए।' सनद रहे कि ट्रंप ने गुरुवार को ट्वीट किया था, 'भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा सीमा शुल्क लगाता है जो अस्वीकार्य है। इसे हटाना होगा।'

मोदी ने ईरान के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया तो ट्रंप शुल्क कटौती पर अड़े

जापान के ओसाका में शुक्रवार को द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप। एएनआइ

मोदी के तर्क
- ईरान से 11 फीसद तेल खरीदता था भारत, जिसे रोक दिया
- खाड़ी देश भारत की ऊर्जा व आर्थिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण

ट्रंप के मुद्दे
- अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क घटाया जाए
- 5जी तकनीक में अमेरिकी कंपनियों मिले मौका

ट्रंप के ट्वीट से भारतीय खेमे में खासी हलचल थी, लेकिन जब ट्रंप अपने भारी भरकम दल के साथ मोदी से मुलाकात के लिए आए तो उनका मिजाज और रुख पूरी तरह बदला हुआ था। आते ही उन्होंने मोदी को अपना दोस्त करार दिया और इस मुलाकात को लेकर कई बार 'पॉजिटिव' शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने भेंट के सकारात्मक असर निकलने की बात कहते हुए कहा, कारोबार के क्षेत्र में जल्द ही भारत-अमेरिका अहम घोषणा करेंगे। बातचीत में 5जी का मुद्दा भी उठा जिसमें अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी तरह चीन की कंपनी हुवेई पर प्रतिबंध लगाए और अमेरिकी कंपनियों की तकनीक का इस्तेमाल करे। मोदी ने भी ट्रंप को बताया कि भारत किस तरह 5जी का इस्तेमाल करता है। यह पूरी दुनिया के दूरसंचार बाजार को प्रभावित करेगा। मोदी ने इस तकनीक में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा देने की जरूरत बताई।

बहरहाल, मोदी की तरफ से भी बेबाकी से उन मुद्दों को उठाया गया जिसको लेकर भारत के हित प्रभावित हो रहे हैं। इनमें ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। मोदी ने बताया कि भारत अपनी जरूरत का 11 फीसद तेल ईरान से खरीद रहा था जिसे उसने रोक दिया है। अब खाड़ी देशों में तनाव की स्थिति से भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा पर असर पड़ने की संभावना है क्योंकि वहां से न सिर्फ भारत बड़ी मात्रा में तेल खरीदता है, बल्कि 80 लाख भारतीय भी वहां रहते हैं। वहां तनाव के मद्देनजर भारत को अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक पोत तैनात करने पड़े हैं। मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध दूरगामी और सकारात्मक विजन के साथ आगे बढ़ें, इसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे।

एस-400 सौदे पर नहीं हुई चर्चा पेज>>11

हमारी सरकार

राम विलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

जिंदगी की पहेलियों से जूझकर संवरा व्यक्तित्व ● पेज 5

कश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा भारत के साथ नहीं, जिम्मेदार कौन : शाह

दावा ▶ जम्मू-कश्मीर को धर्म के आधार पर बांटना देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की सबसे बड़ी भूल

राज्य में राष्ट्रपति शासन छह महीने बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में पारित

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो/एएनआइ/प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दावा किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की सहमति के बिना कश्मीर के एक भाग को पाकिस्तान को दे दिया। उन्होंने राज्य को धर्म के आधार पर बांटने को देश के पहले प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी भूल भी बताया। साथ ही जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 पर कहा कि यह अस्थायी व्यवस्था है, स्थायी नहीं।

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए बढ़ाने के विधेयक पर लोकसभा में चर्चा के दौरान शाह ने कहा 'किसने कश्मीर में सीजफायर का फैसला लिया? ये जवाहर लाल नेहरू ने किया और कश्मीर का बड़ा हिस्सा (गुलाम कश्मीर) पाकिस्तान को दे दिया। आप कहते हैं कि हम लोगों को विश्वास में नहीं लेते हैं, लेकिन नेहरू जी ने उस समय के गृह मंत्री को भरोसे में लिए बिना ये फैसला लिया। इसलिए मनीष जी (मनीष तिवारी) हमें इतिहास मत समझाइए।'

नई दिल्ली में शुक्रवार को लोकसभा में बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (टीवी ग्रैब)। प्रेट्र

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने के लिए मनीष तिवारी द्वारा सरकार की आलोचना करने पर शाह ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, 'वे कह रहे हैं कि हम जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इस समय से पहले, अब तक वहां 132 बार अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) लगाया गया है, इनमें से 93 बार यह कांग्रेस ने किया है। अब ये लोग हमें लोकतंत्र सिखाएंगे?'

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन छह महीने के लिए बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे गावों के लोगों को नियंत्रण रेखा के समीप रहने वाले लोगों की तरह आरक्षण का लाभ देने के दो विधेयकों पर लोकसभा ने मुहर लगा दी।

आतंकवाद के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति : गृह मंत्री शाह ने साफ किया कि मोदी सरकार जम्मू-कश्मीर में इंसानियत, जम्हूरियत, और कश्मीरियत की नीति पर ही काम कर रही है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उसकी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति है। वहां जिसके भी मन में भारत विरोध है, उसके अंदर डर पैदा होना चाहिए।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अंतर : शाह ने आतंकवाद के खिलाफ पहले और अब की लड़ाई में अंतर बताते हुए कहा कि पहले भारत विरोधी बयानबाजी करने वालों को पुलिस सुरक्षा दी जाती थी। हमारी सरकार ने 919 ऐसे लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। गत तीन दशक से आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई कश्मीर घाटी तक सीमित थी, राजग सरकार ने सर्जिकल व एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद की जड़ पर प्रहार किया है।

पहले दो-तीन परिवारों तक केंद्रित थी सत्ता : शाह ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए कई ऐतिहासिक गलतियां जिम्मेदार हैं और इनके मूल पर प्रहार किए बिना वहां स्थायी शांति नहीं आ सकती है। इनमें दो-तीन परिवारों तक सत्ता केंद्रित रखते हुए आम आवाम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने दिया जाना भी शामिल है। मोदी सरकार इन ऐतिहासिक गलतियों को दूर करने का काम कर रही है। हाल ही में चुने गए 40 हजार पंच और सरपंच इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि पहले पंचायत चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में हिंसा का बिल्कुल नहीं होने से साफ है कि कश्मीर में स्थिति सुधर रही है।

अनुच्छेद 370 अस्थायी व्यवस्था पेज>>3

छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, तीन जवान शहीद

- बीजापुर जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र में घात लगाकर किया हमला
- छुट्टी पर जा रहे सीआरपीएफ के जवानों को बनाया निशाना

बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अभियान के दौरान सुरक्षा बल। एएनआइ

नईदुनिया, बीजापुर

छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नक्सलियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 199 बटालियन के तीन जवान शहीद हो गए। हमले के दौरान बीच में फंसे पिकअप वाहन में सवार हल्लूर निवासी जिब्बी तेलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिंकी गंभीर रूप से घायल हो गई। बैकअप पार्टी के पहुंचने के कुछ देर बाद नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग गए।

अधिकारियों के मुताबिक, केशकुतुल कैंप से कुछ जवान छुट्टी पर घर जा रहे थे। वह भैरमगढ़ तक सशस्त्र जवानों की हिफाजत में बाइक से रवाना हुए थे। देवांगन पुलिया के पास पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने बाइक सवार जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले में एएसआइ महादेव पाटिल मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एएसआइ मदनपाल और हेड कांस्टेबल साजी गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हो गए। री-इनफोर्समेंट पार्टी द्वारा उन्हें नजदीक के भैरमगढ़ अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया।

जवानों के हथियार गायब: हमले के बाद मुठभेड़स्थल पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों को जवानों की एक एके 47, एक बुलेटप्रूफ जैकेट, वायरलेस सेट और 120 राउंड कारतूस नहीं मिल रहे हैं। इन्हें नक्सलियों द्वारा लूटकर ले जाने की आशंका जताई गई है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। घटनास्थल पर कई जगह खून के धब्बे देखे गए हैं, जिससे नक्सलियों के भी घायल होने की संभावना जताई जा रही है।

राजनांदगांव में मुठभेड़ के बाद हथियार छोड़कर भागे नक्सली पेज>>6

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

4500 महिला कांस्टेबलों की भर्ती करेगा आरपीएफ

नई दिल्ली : रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में महिलाओं की कमी को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने आरपीएफ में खाली पड़े 9000 पदों में से आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती करने का फैसला लिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान बताया कि रेलवे सुरक्षा बल में अभी महिला कांस्टेबलों (सिपाहियों) की संख्या सिर्फ 2.25 फीसद है। पीएम के निर्देश पर मंत्रालय ने अगली भर्ती में आधे पदों पर महिलाओं की भर्ती का फैसला किया है।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें घटाई

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) और पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) सहित कई लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में 10 आधार अंकों की कटौती कर दी है। केंद्र सरकार के इस कदम से बचतकर्ताओं की आय पर असर पड़ेगा, लेकिन इससे सस्ते कर्ज का रास्ता साफ होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा घोषित नई दरें चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी पहली जुलाई से 30 सितंबर की अवधि के लिए हैं।

क्रिकेट महाकुंभ

अफगानिस्तान vs पाकिस्तान	दोपहर 3:00 बजे से, स्थान : लीड्स
ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड	शाम 6:00 बजे से, स्थान : लंदन

स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क

राहुल के उलाहने पर कांग्रेस में इस्तीफों की बौछार

संजय मिश्र, नई दिल्ली

- महासचिव दीपक बाबरिया समेत राज्यों व एआइसीसी के करीब 150 पदाधिकारियों ने दिया इस्तीफा
- इस्तीफा देने वाले पार्टी नेताओं ने कहा, हार की जिम्मेदारी सबकी

लोकसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेने से कतरा रहे वरिष्ठ नेताओं के रुख पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के उलाहने के बाद पार्टी में इस्तीफों की बौछार शुरू हो गई है। पार्टी महासचिव दीपक बाबरिया, गोवा के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडानकर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और विभिन्न राज्यों के 150 नेताओं ने शुक्रवार को इस्तीफे भेज दिए। दूसरी पंक्ति के नेताओं के इस्तीफों ने दिग्गजों पर भी पद छोड़ने का दबाव बना दिया है। ध्यान रहे कि हरियाणा के नेताओं के साथ गुरुवार को हुई बैठक में राहुल ने दिग्गजों द्वारा हार की जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ने के लिए आगे नहीं आने की बात उठा कर कांग्रेस में खलबली मचा दी। पार्टी में बदलाव का रास्ता बनाने के लिए शुरू की गई इस पहल के बीच कांग्रेस ने फिर दोहराया है कि राहुल को अध्यक्ष बने रहना चाहिए।

मध्य प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव दीपक बाबरिया ने यह कहते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी कि हार के लिए अकेले राहुल नहीं, सभी जिम्मेदार हैं। राहुल के बाद बाबरिया पद छोड़ने की पेशकश करने वाले सबसे बड़े पदाधिकारी हैं और उन्हें राहुल का करीबी भी माना जाता है। कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों के अध्यक्ष, दिल्ली इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया, राष्ट्रीय सचिवों अनिल चौधरी, राजेश धनानी, वीरेंद्र राठौर और प्रकाश जोशी, युवा व महिला इकाई के 150 पदाधिकारियों ने शुक्रवार को सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे दिया। सभी के अनुसार, चुनाव में हार की जिम्मेदारी सबकी है। इसलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं ताकि संगठन में आमूल-चूल बदलाव को पार्टी नेतृत्व अमलीजामा पहना सके। पार्टी की दूसरी पंक्ति के नेताओं की इस पहल ने साफ तौर पर दशकों से कांग्रेस की रीति-नीति संचालित करने वाले दिग्गजों पर पद छोड़ने का दबाव बना दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की चुनाव नतीजे के तत्काल बाद इस्तीफे की पेशकश की टिप्पणी दिग्गजों पर बढ़े दबाव की ओर इशारा करती है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अब कुछ दिग्गजों के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले पर अडिग राहुल ने पार्टी की कमान छोड़ने से पहले संगठन में आमूल-चूल बदलाव का रास्ता खोलने का भी साफ संकेत दे दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नए चेहरे मोहन मरकाम की नियुक्ति कर इसका संकेत दे दिया गया है।

राहुल के फैसला वापस लेने की एक फीसद भी संभावना नहीं : मोइली पेज>>3

मुस्लिम बच्चों के लिए अलग भोजन कक्ष पर विवाद बढ़ा तो ममता सरकार ने लिया यू-टर्न

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- भाजपा ने तुष्टीकरण व विद्यार्थियों को धर्म के आधार पर बांटने का लगाया था आरोप

पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक और मदरसा शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए अलग भोजन कक्ष बनाने संबंधी निर्देश पर विवाद गहराता देख ममता सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही यू-टर्न ले लिया है। सरकार की ओर से जारी नए निर्देश में कहा गया है कि सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि सभी विद्यार्थियों के लिए भोजन कक्ष बनाया जाएगा।

इससे पहले जारी निर्देश में ममता सरकार ने मदरसों, प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों से मुस्लिम छात्र-छात्राओं की संख्या से संबंधित जानकारी मांगी थी। निर्देश में यह भी कहा गया था कि 70 फीसद या उससे अधिक मुस्लिम छात्र-छात्राओं वाले स्कूलों में राज्य सरकार की ओर से मुस्लिम छात्र-छात्राओं के लिए अलग से भोजन कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। इसे लेकर भाजपा, माकपा और कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। चौतरफा आलोचना झेलने के बाद ममता सरकार को बाध्य होकर निर्देश को बदलना पड़ा।

ममता बनर्जी फाइल फोटो

ममता बोलीं, उद्देश्य छात्रों को बांटना नहीं : इस निर्देश पर विवाद बढ़ता देख ममता ने सफाई पेश की थी। उन्होंने बयान जारी कर कहा था कि आदेश का उद्देश्य छात्र-छात्राओं को बांटना नहीं है। सर्कुलर को इस तरह से लिखा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं ज्यादा संख्या में है ताकि अल्पसंख्यक वेलफेयर डिपार्टमेंट फंड को योजना में समाहित किया जा सके। यह तकनीकी मामला है, जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने आगे कहा, विभिन्न विभागों से फंड इकट्ठा करने का विचार है ताकि योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा सके।

भाजपा, कांग्रेस और माकपा ने ममता सरकार को घेरा पेज>>4

अजब हाल

जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, 2022 तक रुक जाएगा गंगा में सीवेज का गिरना, उमा भारती ने किया था 2020 तक गंगा में सीवेज गिरने से रोकने का दावा, गडकरी ने किया था मार्च 2020 तक गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने का एलान

मंत्री बदलते ही बदल जाता है गंगा की सफाई का लक्ष्य

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

सरकार ने गंगा में सीवेज गिरने से रोकने का लक्ष्य बदल दिया है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि 2022 तक गंगा में सीवेज गिरने से रुक जाएगा। उनका कहना है कि सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। शेखावत का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2020 तक गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने का एलान किया था। वहीं उनसे पूर्व इस मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहीं तत्कालीन जल संसाधन मंत्री उमा भारती 2020 तक गंगा में सीवेज गिरने से रोकने का लक्ष्य बताया था।

शेखावत ने शुक्रवार को उद्योग संगठन एसोचैम में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि गंगा नदी में साफ किए बगैर सीवेज का गिरना 2022 तक पूरी तरह रुक जाएगा। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड और झारखंड इस लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। हालांकि शेखावत के इस बयान पर गंगा की सफाई के लिए संघर्ष कर रहे गैर सरकारी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गंगा महासभा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती का कहना है, 'गंगा की वास्तविक स्थिति का आकलन किए बगैर, हवा-हवाई आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालकर 2020 या 2022 तक निर्मल प्रवाह की बात करना, गंगा के साथ अन्याय है। मंत्री बदलते ही लक्ष्य बदल जाना यह अपरिपक्व कार्यशैली का उदाहरण है। इससे गंगा की सफाई के बारे में संदेह उत्पन्न होता है।'

नई दिल्ली में शुक्रवार को ओखला बैराज के समीप कालिंदी कुंज घाट पर यमुना नदी की सफाई अभियान में हिस्सा लेते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। एएनआइ

गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 13 मई 2015 को नमामि गंगे योजना को मंजूरी देकर इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया। इसके बाद तत्कालीन केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने 21 जुलाई 2016 को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा था कि एनजीआरबीए फ्रेमवर्क के तहत 2020 तक गंगा नदी में अनट्रीटेड सीवेज को गिरने से रोकने का लक्ष्य है। हालांकि 2017 में यह विभाग उमा से लेकर गडकरी को सौंप दिया गया। इसके बाद गडकरी ने भी 27 दिसंबर 2018 को कहा था कि मार्च 2019 तक गंगा 70 से 80 फीसद साफ हो जाएगी और मार्च 2020 तक लगभग पूरी तरह प्रदूषणमुक्त हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि तत्कालीन संप्रग सरकार के दौरान राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी ने पांच अक्टूबर 2019 को पहली बैठक में लक्ष्य रखा था कि 2020 तक गंगा में साफ किए बगैर म्युनिसिपल सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट नहीं डाला जाएगा।

राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष से ही भिड़ गए गहलोत के दो मंत्री

जागरण संवाददाता, जयपुर

- संसदीय कार्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का अध्यक्ष से हुआ विवाद

राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की इजाजत न मिलने पर संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी से भिड़ गए। इससे खफा जोशी सदन की कार्यवाही स्थगित किए बिना ही चले गए। बाद में सदन में लौटे और कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित करके चले गए। वहीं सदन में बोलने का मौका न दिए जाने से खफा चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा जोशी के चैंबर में पहुंच गए, जहां दोनों के बीच तीखी तकरार हुई।

जानकारी के अनुसार, विधानसभा में शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने अवैध बजरी खनन को लेकर सरकार पर कई आरोप लगाए। शांति धारीवाल ने जवाब देना चाहा, लेकिन जोशी ने अनुमति नहीं दी। धारीवाल के नाराजगी जताने पर जोशी ने कहा कि मैं सदन छोड़कर जाऊं। इसके बाद वह सीट छोड़कर चल दिए। कुछ ही क्षण में उन्हें सदन स्थगित नहीं करने की याद आई तो फिर सीट पर आकर आधा घंटे के लिए सदन स्थगित करने की बात कही और अपने चैंबर में चले गए।

इसके बाद चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा विधानसभा अध्यक्ष के चैंबर में पहुंचे और जोशी को बोलने का मौका न देने का उलाहना दिया। अध्यक्ष ने शर्मा को अगले दिन नियम के तहत बात कहने की बात कही तो उन्होंने कहा कि जब आरोप आज लगे हैं तो कल क्या होगा। इसी बात पर दोनों में नोकझोंक हो गई। बाद में डॉ. रघु शर्मा ने मीडिया से कहा, सदन में विपक्ष के विधायक एनएचएम घोटाले को लेकर मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे थे। मैं उनके आरोपों का जवाब देना चाहता था, लेकिन अध्यक्ष ने बोलने की अनुमति नहीं दी। मैंने अध्यक्ष के समक्ष अपना विरोध दर्ज करा दिया है। उन्होंने कहा, विधानसभा अध्यक्ष के रवैये की शिकायत सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री से करूंगा।